



सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा 2018-19

खण्ड 1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: cordecndn-dea@nic.in
जुलाई, 2019

विषय सूची

अध्याय सं०	पृष्ठ सं०	अध्याय का नाम
	vii	आभारोक्ति
	ix	प्राक्कथन
	xi	संकेताक्षर
1		परिवर्तन का दौर: विकास, रोजगार और मांग में तेजी लाने का मुख्य प्रेरक निजी निवेश
	2	पिछले पांच वर्ष: उपलब्धियाँ
	4	आगामी पांच वर्ष: संवृद्धि और रोजगार सृजन की कार्ययोजना
	10	मूल योजना में “संतुलन” के अर्थशास्त्र से आगे जाना
	12	निरंतर अस्थिरता में आगे बढ़ना
	17	महत्वपूर्ण संवाहक, सुधार एवं जोखिम कारक
2		अर्थलिप्सा के लिए नहीं अपितु मानव जाति के लिए नीति-व्यावहारिक अर्थव्यवस्था में “टहोका”
	29	सरकारी नीतियों का प्रभाव मंडल
	32	भारत में व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टियों के सफल अनुप्रयोग
	40	सार्वजनिक नीति के लिए व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टि को लागू करने के संबंध में सिद्धांत
	41	पथ प्रवर्तक बदलाव के लिए आकांक्षापूर्ण कार्य सूची
	54	व्यवहारात्मक परिवर्तन के लिए आकांक्षा पूर्ण कार्य सूचियों का कार्यान्वयन
3		छोटों को पोषित कर, उन्हें विशाल बनाना: एमएसएमई वृद्धि के लिए नीतियों को नई दिशा देना
	57	प्रस्तावना
	58	बौनेपन का अभिशाप और रोजगार तथा उत्पादन पर इसका प्रभाव
	62	बौनेपन को बढ़ावा देने में नीति की भूमिका
	74	भावी संभावनाएं
4		डाटा ‘लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए
	78	आंकड़ों (डाटा) और सामाजिक कल्याण का अर्थशास्त्र
	81	डाटा को सार्वजनिक संपत्ति क्यों माना जाना चाहिए?
	83	सिस्टम का निर्माण
	90	भारत के डाटा अवसंरचना का रूपांतरण
	93	एप्लीकेशन
	95	भावी परिदृश्य

5	मत्स्य न्याय का समापन: निचली न्यायपालिका की क्षमता कैसे बढ़ाएं
98	प्रस्तावना
100	लंबित मामले
100	निपटान
102	मामला निस्तारण दर
103	क्या विधिक गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है?
105	अतिरिक्त न्यायाधीश कैसे आवंटित किए जाएं?
111	भारतीय न्यायालयों को और अधिक कार्यशील बनाना
6	नीति की अनिश्चितता निवेश को कैसे प्रभावित करती है?
115	परिचय
117	भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता
120	वर्ष 2015 से भारत में आर्थिक नीति अनिश्चितता का पृथकीकरण
121	निवेश क्रिया कलापों में उलट-फेर के फायदे
122	भारत में आर्थिक नीति की अनिश्चितता और निवेश में संबंध
125	निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें
7	वर्ष 2040 में भारत की जनसंख्या: 21वीं शताब्दी के लिए सरकारी प्रावधान की आयोजना
128	हाल के जनांकिकीय रूझान
132	राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जनसंख्या अनुमान
139	वृद्धता संचार के नीतिगत निहितार्थ
146	निष्कर्ष
8	स्वच्छ भारत के माध्यम से स्वच्छ भारत से सुंदर भारत: स्वच्छ भारत मिशन का एक विश्लेषण
148	प्रस्तावना
149	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम)
152	ओडीएफ स्थिति के संबंध में सभी राज्यों की तुलना (% में)
154	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
154	स्वच्छ भारत मिशन का स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रभाव
157	एसबीएम के प्रभाव: कुछ स्वतंत्र अध्ययन
160	भावी राह
9	किफायती, भरोसेमंद और सतत् ऊर्जा के माध्यम से समावेशी विकास को संभव बनाना
163	परिचय
164	समृद्धि के लिए ऊर्जा
166	ऊर्जा उपलब्धता-ऊर्जा गरीबी

169	ऊर्जा दक्षता
172	ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का प्रभाव
172	विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा बचत क्षमता
174	ऊर्जा उत्पादन की निरंतरता
175	अक्षय ऊर्जा क्षमता,
176	भारत में बिजली चालित वाहन
180	भावी परिदृश्य
10	कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग-मनरेगा का मामला
183	प्रस्तावना
185	मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग
188	डी.बी.टी. का मनरेगा की प्रभावकारिता पर प्रभाव
193	स्थानापन्न संकट में उपभोग संबंधी आंकड़ों का उपयोग
195	भावी परिदृश्य
11	समावेशी विकास के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करना
199	परिचय
200	भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली
200	राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी
200	भारत में जटिल न्यूनतम मजदूरी प्रणाली
202	राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी: क्या यह न्यायोचित है?
202	न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों में लिंग भेद का आभास
204	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन
206	न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव
209	भावी परिदृश्य

आभारोक्ति

यह आर्थिक समीक्षा मिलजुल कर किए गए कार्य एवं परस्पर सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की मूल्यवान टिप्पणियों तथा उनकी अंतरदृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से भी लाभान्वित हुई है जिनमें विशेष रूप से सर्वश्री सुभाष चंद्र गर्ग, अजय भूषण पांडे, के० राजा रामन, अमरजीत सिन्हा तथा अवनीश चावला शामिल हैं।

इस समीक्षा में आर्थिक प्रभाग के संजीव सान्याल, सुष्मित दासगुप्ता, अरुण कुमार झा, अरुण कुमार, राजीव मिश्र, राजश्री रे, सुरभि जैन, ए० प्रतिभा, एस० अर्पुतास्वामी, निखिला मेनन, अश्विनी लाल, अभिषेक आचार्य, रजनी रंजन, सिंधुमन्निक्कल थंकप्पन, प्रेरणा जोशी, धर्मेन्द्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, एम० राहुल, रवि रंजन, तुलसीप्रिया राजकुमारी, शमीम आरा, जे० डी वैशम्पायन, आर्य बी० के०, अभिषेक आनंद, सोनल रमेश, संजना काद्यान, अमित श्योरन, श्रेया बजाज, सुभाष चंद्र, रियाज अहमद खान, मोहम्मद आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पाईन, नरेंद्र जेना, श्रीवत्स कुमार परीदा, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा तथा अमित कुमार केशरवानी, अर्पिता वायकरे, नवीन वाली, महिमा, अंकुर गुप्ता, लिपि बुद्धिराजा, सोनम गायत्री मल्होत्रा, लविशा अरोड़ा का भी योगदान रहा है।

यह समीक्षा विशेष रूप से इन अधिकारियों से मिली टिप्पणियों तथा इनपुट से भी लाभान्वित हुई हैं, प्रणब कुमार मुखोपाध्याय, महानिदेशक, डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, श्री अजय श्रीवास्तव, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, सुश्री श्रुति शुक्ला, संयुक्त निदेशक, डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, डॉ० एम० डी० पात्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), श्री राजन गोयल, सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), प्रोफेसर क० एस० जेम्स, प्रोफेसर चंद्रशेखर, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, प्रोफेसर सुरेश शर्मा तथा वंदना शर्मा, आर्थिक विकास संस्थान, श्री राजीव जैन, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री धीरेन्द्र गजभिए, सहायक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), श्री सूर्यप्रकाश बी० एस०, अध्येता तथा कार्यक्रम निदेशक (दक्ष); सिद्धार्थ मांडरेकर राव, शोध सहयोगी (दक्ष), सुश्री सौमाश्री तिवारी, अनुसंधान अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री सुखवीर सिंह, सी ए ए ए, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री अभय बकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, डॉ० अशोक कुमार, निदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, डॉ० सूर्या पी० सेठी तथा श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय।

यह आर्थिक समीक्षा टीम, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड, ई-कोर्ट पोर्टल यूके-इंडिया ई पी पी पी तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली से प्राप्त इनपुट के लिए भी अपना आभार व्यक्त करती है। हम विभिन्न शिक्षाविदों तथा चिकित्सकों से प्राप्त टिप्पणियों और इनपुट के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनमें तनुज भोजवानी, साजिद चिनाँय, मोहनदास पाई, हर्षिनी शंकर, शरद शर्मा, प्रसन्ना तंत्री तथा के० वैद्यनाथन शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई मंत्रालयों ने अपने इनपुट प्रदान करने के लिए प्रेजेंटेशन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सीधे मुख्य आर्थिक सलाहकार से संपर्क साधा। आर्थिक समीक्षा टीम उनके मूल्यवान समय, प्रतिबद्धता और योगदान के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

श्री के० राजारामन, राजकुमार तिवारी, जसवीर सिंह, सुरेश कुमार, अनुपम शुक्ला, साधना शर्मा, अरुण गुलाटी, सुशील शर्मा, मनीष पेंवार, मुन्ना साह, सुरेश कुमार, जोध सिंह ओमवीर सिंह, आर आर मीणा, सुभाष चंद्र, राजकुमार, रामनिवास, केशर सिंह, बालकिशन, सतीश कुमार, गजेंद्र सिंह तथा आर्थिक प्रभाग एवं कार्यालय: मुख्य आर्थिक सलाहकार के अन्य स्टाफ ने भी कुशल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया।

प्रोफेसर वी० एस० वागला के साथ मिलकर निहारिका सिंह, संतोष कुमार मिश्रा, सुभाष चंद्र अवरस्थी, निकोलस खाल्को, पवित्र जायसवाल, अर्चना सिंह, अनिता कुमारी, संजीव शर्मा, दीपक डागर, राकेश बंगालिया तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के ओमप्रकाश सिंह, मुरारी लाल गुप्त, जगत सिंह रोहिल्ला, जनवारियुस तिकी, जय वीर, डॉ० गौतम शर्मा, मनीष भटनागर, अजय कुमार चौधरी, अनुप साव ने इस आर्थिक समीक्षा का हिन्दी अनुवाद कार्य किया। हिंदी टंकण कार्य, पंकज कुमार, अनिल गोसाई, संजय प्रसाद, सुरेश आहूजा, नीरू कपूर, मीना पंत, विजया दीवान द्वारा किया गया। समीक्षा का मुखपृष्ठ इंडिया ब्रांड इक्विटी

फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया। मेसर्स विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने इस समीक्षा के हिंदी-अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण कार्य किया।

अंत में हम इस आर्थिक समीक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय दिया है साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना अदम्य भावनात्मक सहयोग और प्रोत्साहन भी दिया। आर्थिक समीक्षा में समर्पित सहयोगियों के लिए उनके परिवार सदैव शक्ति के मूक स्तंभ रहे हैं।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्राक्कथन

आरंभ में, हम पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारत के आर्थिक कैलेंडर में और अधिक प्रत्याशित घटनाचक्र के लिए आर्थिक समीक्षा को उच्चस्तरीय बनाया है। उन्होंने अपनी विद्वता, तपस्या के जरिए अमूल्य योगदान दिया है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी विचारधारा है जिसे केवल सर आईजक न्यूटन के अनश्वर भावों में ही व्यक्त किया जा सकता है: “यदि मैं औरों की अनदेखी करके, आगे की ओर देखता हूँ तो लगता है कि जमीन नहीं आसमान की ओर देखकर चलता हूँ” समीक्षा के ऐसे शानदार संकलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी नम्रता पूर्वक प्रयास किए गए हैं।

प्रचण्ड जनादेश के साथ सत्ता में आई नई सरकार की यह पहली समीक्षा है। मुख्यतः युवा जनसंख्या हमसे काफी महत्वाकांक्षी है, भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, जब भारत ने अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को बरकरार रखते हुए इसे राष्ट्रीय परिवेश के अनुकूल बनाया है। समुचित रूप से माननीय प्रधान मंत्री ने 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना निर्धारित किया है (#Economy@5trillion) और प्रत्येक नागरिक को इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, अपना-अपना अंशदान करने के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं:- “130 करोड़ भारतीयों द्वारा विकास के लिए उठाया गया एक-एक कदम देश को कई-कई कदम आगे बढ़ाएगा”। इस स्वप्न को साकार करने की दृष्टि से नीतिगत कार्य योजना तैयार करके, समीक्षा ने एक सामूहिक प्रयास करने हेतु असीम प्रतिबद्धता दर्शाई है: स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर हम 130 करोड़ भारतीय एक राष्ट्र के रूप में, 2022 तक एक विशेष भारत का निर्माण करेंगे (#Economy@5trillion)।

अवसर की शक्ति से ओत-प्रोत प्रकाश, आर्थिक समीक्षा 2018-19 की टीम के लिए ‘नीले गगन के समान’ विस्तृत विचारधारा से प्रेरित है। समीक्षा ने भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल के बारे में विचार करते हुए एक उन्मुक्त दृष्टिकोण अपनाया है। यह प्रयास समीक्षा के [स्काई ब्लू कवर](#) में प्रतिबिंबित होता है। #Economy@5trillion के स्वप्न को साकार करने के लिए भारत को अपने उपकरण अर्थात वास्तविक जीडीपी की 8 प्रतिशत बढ़त दर में परिवर्तन लाना होगा और उसे सतत रूप से बनाए रखना होगा। समीक्षा की पारंपरिक सोच को छोड़कर, जिसमें अर्थव्यवस्था या तो गुणकारी चक्र में होती या दुराचारी चक्र में होती, हमें कभी भी समतुल्यता की दृष्टि से न देखते हुए या तो आर्थिक बढ़त, मांग, निर्यात और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पृथक समस्या मानने के बजाए यह समीक्षा वृहत अर्थशास्त्र संबंधी इन स्थितियों को एक दूसरे के पूरक की दृष्टि से देखती हैं। कवर डिजाइन, बहुत से अंतर-संबंधी परिवर्तनों के चित्रात्मक विवरण से इन वृहत अर्थशास्त्र संबंधी चरवस्तुओं के बीच अनुपूरक अंतर-संबंधों संबंधी विचारधारा को प्रतिबिम्बित करता है।

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए मार्गों पर चलते हुए जिनसे लंबी अवधि तक उच्च बढ़त का अनुभव प्राप्त हुआ है, यह समीक्षा निवेश की केन्द्रीयता को “प्रमुख प्रेरक” के रूप में मानता है जो अनुकूल जन सांख्यिकीय चरण के होते हुए अर्थव्यवस्था को स्वतः ही गुणकारी चक्र को बनाए रखने हेतु प्रेरित करता है। #Economy@5trillion के स्वप्न को साकार करने के लिए कार्यनीतिक ब्लूप्रिंट बनाने के बाद सर्वेक्षण कुछ कौशल उपकरणों का विवरण देता है जो निरंतर असाम्यता की स्थिति में एक अनिश्चित दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने हेतु जरूरी है। यह समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन करने और अधिक उत्पादक बनने हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पोषण करने पर ध्यान केन्द्रित करती है ताकि वे कानूनी सुधार को बढ़ावा देकर, एक ध्येय और कार्यनीतिक ब्लूप्रिंट के साथ नीति की निरंतरता सुनिश्चित करके, पूंजी की लागत में कमी लाकर और निवेशों हेतु जोखिम-प्रतिलाभ (Risk-return) अदला-बदली को तर्कसंगत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना जा सके।

अपने स्वच्छंद विचारों के प्रयत्न में, इस समीक्षा में पिछले कुछ दशकों में “व्यवहार-अर्थशास्त्र” के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास को उपयोग किया गया है, जिसकी पराकाष्ठा के लिए प्रोफेसर रिचर्ड थेलर को आर्थिक-विज्ञान के लिए वर्ष 2017 में नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है। सरकार की प्रमुख पहलों जैसेकि स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना और बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ योजना का विशाल प्रभाव इस बात का साक्ष्य है कि भारत में व्यावहारिक परिवर्तन किए जा सकने की अनेक संभावनाएं हैं। हमारी प्रदत्त संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के कारण सामाजिक प्रतिमान हम में से हर एक के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहार-अर्थशास्त्र हमें न केवल उन साधनों व सिद्धांतों को उपलब्ध करवाता

है जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार 'प्रतिमान' को प्रभावित करते हैं, बल्कि उस विधि को भी बताता है जिसके द्वारा उन प्रतिमानों के उपयोग से किस प्रकार व्यावहारिक परिवर्तनों को लाया जा सकता है। इसलिए यह समीक्षा व्यावहारिक परिवर्तन के लिए एक उच्चाकांक्षी कार्य-सूची को प्रदर्शित करता है जिसमें व्यवहार-अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनेक मुद्दों में किया गया है जिनमें लिंग समानता, स्वस्थ और सुंदर भारत मितव्ययिता और कर अनुपालनात्मकता और ऋण गुणवत्ता शामिल है।

हम ऐसी सदी में प्रवेश कर रहे हैं जहां निर्णयन प्रक्रिया के लिए संसाधित डाटा अपरिहार्य हो गया है, जिस प्रकार संसाधित तेल को ही उपयोग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार संसाधित डाटा का ही उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण से इस सर्वेक्षण द्वारा "डाटा" को लोक कल्याण के साधक के रूप में सृजित किया जा रहा है, जहां सरकार का चयन जनता द्वारा किया जाता है, सरकार जनता के लिए नियम बनाती है और जनता के लिए नियमों में परिवर्तन भी किया जाता है।

इस समीक्षा रिपोर्ट को तैयार करने में आवश्यक स्तरीय परिशुद्धता को अनुरक्षित करते हुए, 'समय' और 'प्रतिभा' को अर्पित किया गया है जिससे हमारा विश्लेषण सभी पाठकों के लिए बोधगम्य बन सके। सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूक्ष्मदृष्टि तथा पाठकों के लिए गूढ़ संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के प्रयोजन से समीक्षा के प्रत्येक अध्याय से संबंधित 'सारांश' और "अध्याय एक झलक" को सम्मिलित किया गया है।

हमने समीक्षा को दो खंडों में प्रस्तुत करने की लोकप्रिय परंपरा को जारी रखने का चयन किया है। खंड-I में हमने नीले आकाश के समान व्यापक मनोभावों को संकलित करने का प्रयास किया है और इसके साथ-साथ इसमें नवीनतम आर्थिक विकास कार्यों के आर्थिक विश्लेषणों के साक्ष्यों को भी उपलब्ध करवाया है जिससे हम उन नीति-निर्माताओं को सक्षम बना सकें जो सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं।

खंड-II में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई है और इसके समर्थन में प्रासंगिक सांख्यिकीय तालिकाएं एवं डाटा उपलब्ध करवाया गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान प्रास्थिति तथा नीतियों के लिए सुलभ पूर्वानुमान के रूप में लाभदायक होगी।

इस आर्थिक समीक्षा के अस्तित्व और लोकप्रियता का श्रेय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, आर्थिक सेवा के अधिकारियों के विलक्षण संसाधन आधार, शोधकर्ताओं, सलाहकारों, सरकारी और बाह्य दोनों क्षेत्रों के प्रबुद्ध मंडल/विशेषज्ञ दल के बहुमूल्य परामर्श तथा आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को जाता है। इस समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने, इसे समझने और इसके बारे में चिंतन की दिशा में अपरिहार्य मार्गदर्शक बनने की अभिलाषा पर खरा उतरने का निश्चल प्रयास किया गया है। यद्यपि हमारे अथक प्रयास ही हमारे अंतिम पारितोषिक के द्योतक हैं फिर भी, हमें पूरी आशा है कि सुधी पाठकगण भी उसी उत्कृष्टता का अनुभव करेंगे जिसके प्रयोजनार्थ हमने इस समीक्षा को प्रस्तुत किया है।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

एजीडीएसएम	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन	जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
एएनबीसी	समायोजित नेट बैंक क्रेडिट	जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस	जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर	जीवीए	वर्धन सकल मूल्य
एपीएल	आधार से लिंक किए गए भुगतान	एचडीआई	मानव विकास सूचना
एसएसआई	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	एचआरडी	मानव संसाधन विकास
बीएयू	हमेशा की तरह व्यापार	आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
बीबीबीपी	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
बीसीई	ईसा पूर्व	आईसीटी	सूचना व संचार प्रौद्योगिकी
बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	आईडीए	औद्योगिक विवाद अधिनियम
बीईवी	बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन	आईएचएल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
बीएचआईएम	भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी	आईआईपीएस	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान
बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे	आईएलसी	अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
ब्रिक्स	ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका	आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन
कैफे	कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता	आईएमडी	भारत मौसम विभाग
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	आइवीए	स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी
सीसीआर	केस क्लियरेंस रेट	जेएएम	जन धन, आधार और मोबाइल
सीडपीइजे	न्याय दक्षता आयोग	कुसुम	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाअभियान
सीओ	कार्बन डाइऑक्साइड	एलसीआर/आर एंड पी	निचली अदालत रिकार्ड्स/अभिलेख और कार्यवाही
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	एलईडी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
सीएससी	सामूहिक सेवा केन्द्र	एलएफआर	श्रम बाल भागीदारी दर
सीवी	गुणांक का परिवर्तन	एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
डी एंड एस कोर्ट	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	एमएए	माता का पूर्ण स्नेह
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
डीबीटीएल	एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	एमआईएस	सूचना प्रबंधन प्रणाली
डीसी	नामित उपभोक्ता	एमओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
डीडीयू जी.के.वाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	एमओईएफ एण्ड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
डीस्कॉम	वितरण कंपनियां	एमओयू	समझौता ज्ञापन
डीएसएम	मांग पक्ष प्रबंधन	एमपीसीई	मासिक प्रति व्यक्ति आय
ई-नाम	राष्ट्रीय कृषि बाजार	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
ईसीबीसी	ऊर्जा संरक्षण भवन कोड	एमटी सीओटू	कार्बन डाइऑक्साइड के मीट्रिक टन समतुल्य
ईसीसी	रोजगार स्थिति आयोग	एमटीओई	तेल समतुल्य का मिलियन टन
ईईएसएल	ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड	एनएआरएसएस	राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण
इओडीबी	व्यापार करने में आसानी	एनबीएफसी एए	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खाता एग्रीगेटर्स
इपीयू	आर्थिक नीति अनिश्चितता	एनडीसी	राष्ट्रीय निर्धारित योगदान
इएससी	ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र	एनईएफएमएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली
इयूएस	रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण	एनइएमएमपी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना
ईवीएस	विद्युत वाहन	एनइवी	नई ऊर्जा वाहन
एफएमएम	द्रीव्तर स्वीकार्य और विद्युत वाहनों का विनिर्माण	एनएफएलएमडब्ल्यू	राष्ट्रीय तल स्तर न्यूनतम वेतन
एफसीईवी	ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन	एनजेडीजी	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेश	एनआरएम	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	एसएलडब्ल्यूएम	टोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एनवीए	सकल मूल्य वर्धन	एसआरबी	जन्म के समय लिंग अनुपात
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त	एसएसआई	लघु स्तर उद्योग
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन	टीएफआर	कुल प्रजनन दर
ओएलएस	सामान्य से कम चौकोर	टीओई	तेल समतुल्य का टन
ओआरएस	मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान	टीडब्ल्यूएच	टेरावाट घंटे
ओएसएच	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य	यूईई	संयुक्त अरब अमीरात
पैन	स्थायी खाता नम्बर	यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
पीएटी	उपार्जित और व्यापार	उजाला	किफायती एलइडी के द्वारा उन्नत ज्योति
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	यूके	यूनाईटेड किंगडम
पीएचइवी	प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन	यूएलवी	शहरी स्थानीय निकाय
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना	यूपीआई	यूनाईटेड भुगतान इंटरफ़ेस
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय	यूएसए	संयुक्त राज्य अमरीका
पीएसएल	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा	वीडीए	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन	डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	जेडईवी	शून्य उत्सर्जन वाहन
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य		